जेट एयरवेज अगर टाटा ने न खरीदा तो क्या होगा लाला बैंक और मोदी सरकार का निकलेगा दिवाला

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

मुंबईः देश की एक और एयरलाइंस जेट एयरवेज डूबने के कगार पर है और देश का एक और बड़ा घोटाला सामने आने को तैयार है। तीन दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट से उसके 10 विमान उड़े ही नहीं। वजह यह कि वेतन न मिलने की वजह से पायलट ड्यूटी पर आए ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एयरलाइंस को बैंक से कर्ज लेकर ठीक उसी तरह खड़ा किया गया था, जिस तरह भगोड़े विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को खड़ा किया गया था। बैंकों में जमा जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को विजय माल्या और नरेश गोयल जैसे बदनाम उद्योगपतियों का साम्राज्य खड़ा करने में झोंक दिया गया। जेट एयरवेज का मालिक इस वक्त कभी दुबई में रहता है तो कभी लंदन में रहता है। दो साल हो गए, जब उसने राष्ट्रवादी भारत की धरती को चूमा था। अब अगर जेट एयरवेज को टाटा ने खरीद लिया तब तो नरेश गोयल को भारत आकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन अगर टाटा ने नहीं खरीदा और बैंकों से और कर्ज नहीं मिला तो नरेश गोयल लंदन या दुबई में आराम फरमाएगा और भारतीय जांच एजेंसियां लंदन या दुबई में उसे भारत लाने के लिए वहां की अदालतों में हाथ-पैर मार रही होंगी।

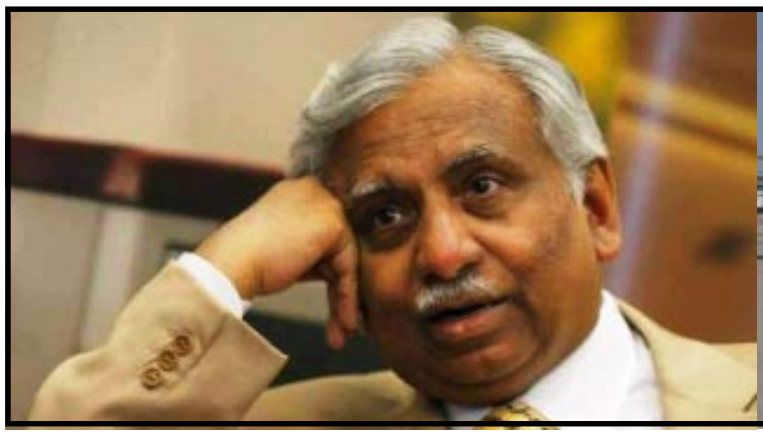

दाऊद इब्राहीम...भाजपा...नरेश गोयल

भारत की जनता पूंजीवादी राजनीतिक दलों की करतूत भूलने में माहिर है। यूपीए के कार्यकाल में जेट एयरवेज खड़ी हुई थी। डॉ. मनमोहन सिंह की उदार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब बैंकों से कर्ज की रेवड़ियां बांटी जा रही थीं, उसी समय जेट वेयरवेज को भी कर्ज मिला। लेकिन उस वक्त भाजपा ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहीम की फंडिंग है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच कराई लेकिन निकला कुछ नहीं। हालांकि नरेश गोयल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पुराने थे। भाजपा यह आरोप 2014 तक लगाती रही थी। लेकिन जैसे ही केंद्र में उसने सत्ता संभाली, दाऊद का नाम गायब हो गया। नरेश गोयल की प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच हो गई। 2015 में केंद्र सरकार के दबाव पर बैंकों ने जेट एयरवेज को बड़ा लोन दिलवाया। भाजपा सरकार ने आते ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप का जो हौव्वा खड़ा किया, उसकी आड़ में बैंकों को दबाव में दनादन लोन बांटने पड़े।

किसी भी धंधे की बैंक फंडिंग इस आधार पर होती है कि आज बैंक आपके काम आया है, कल को आप कमाकर उसे पैसा ब्याज समेत वापस कर देंगे। तभी बैंकिंग सिस्टम और कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कारगर होगी। लेकिन एयरलाइंस मुनाफा कमाएंगी तभी तो पैसा वापस करेंगी। लेकिन किंग फिशर और जेट एयरवेज खड़ी करने वाले मालिक इतने अय्याश थे कि उन्होंने पूरा बिजनेस ही गुड़ गोबर कर दिया। उसी दौरान खड़ी की गई इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी कंपनी किंगफिशर और जेट एयरवेज से ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से चलाई गईं और उनका प्रदर्शन फिलहाल बेहतर जा रहा है।

नरेश गोयल को 2015 में मोदी सरकार ने जो लोन दिलवाया, उसमें कई झूठ बोले गए थे, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जैसे 2014 तक जेट एयरवेज अपने लोन का पूरा ब्याज तक नहीं चुका पाई थी, इसके बावजूद उसे बैंकों ने लोन दिया। नरेश गोयल ने जेट में अपनी 51 फीसदी की पूरी शेयरहोल्डिंग को पंजाब नैशनल बैंक के पास 2015 में गिरवी रख दिया था जिसकी कीमत उस वक्त 2600 करोड़ रुपये आँकी गयी थी और उस वक्त गोयल द्वारा शेयरों को गिरवी रखे जाने के निर्णय की वजह की जानकारी नहीं दी गई थी ।यानी कंपनी के शेयर होल्डरों तक को यह जानकारी नहीं थी। लेकिन अक्टूबर-नवंबर में जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का मायाजाल सामने आया तब इसका पता चला। लेकिन अब इसकी तारीख 8 जनवरी 2018 बताई गई है। लेकिन यह गोरखधंधा 2015 का है।

जेट एयरवेज द्वारा फाइल की गई एक रेग्युलेटरी में कहा गया है कि गोयल ने एयरलाइन में अपने सभी 57933665 शेयरों यानि कि 51 फीसदी हिस्सेदारी को एक नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग के साथ पीएनबी के पास गिरवी रखने का निर्णय किया है, जोकि 8 जनवरी से प्रभावी हुआ है।

गोयल द्वारा शेयरों को गिरवी रखे जाने के निर्णय की वजह की जानकारी नहीं दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एथिहाद के जेट एयरवेज में सामरिक साझीदार के तौर पर 24 फीसदी शेयर हैं, जबकि बाकी शेयर्स अन्य रिटेल इन्वेस्टर्स और संस्थाओं के पास हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटे में चल रही जेट एयरवेज पर सितंबर 2014 में समाप्त हुई तिमाही तक 9794 करोड़ रुपये का ऋण था, जो मार्च 2014 की तिमाही के 10756 करोड़ रुपये ऋण की तुलना में 7 फीसदी कम था। इससे एयरलाइन को दूसरी तिमाही में अपने ब्याज के बोझ को 15 फीसदी यानि 212.75 करोड़ तक घटाने में मदद मिली।

यह क्यों छिपाया आखिर

एयरलाइन ने यह नहीं बताया है कि उसने पीएनबी से कितना रुपया उधार लिया था। इस बारे में तुरंत बैंक की प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी है। 1 दिसंबर से अपनी लो-कॉस्ट ब्रैंड जेटलाइट की सेवाएं बंद करने वाली जेट एयरवेज ने एक ही सौदे से अपने कुल घाटे में 96 फीसदी की कमी की जानकारी दी थी। इस सौदे के तहत इसने जेपीमाइल्स को एथिहाद को बेच दिया था।

अपने इक्विटी पार्टनर एथिहाद से लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत सेल से हुई वन-टाइम इनकम से मिले 305 करोड़ रुपये से घाटे को तीन महीने के अंदर सितंबर तक घाटे को 95.7 फीसदी तक लाने में मदद मिली थी। इससे एक साल पहले समान अवधि में एयरलाइन ने 999 करोड़ रुपये घाटे की जानकारी दी थी।

2012 के बाद से पहली बार नरेश गोयल प्रमोटेड एयरलाइन ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से स्टैंडअलोन बेसिस पर वन-टाइम इनकम की मदद से 69.82 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट की घोषणा की थी। सकल आय इस तिमाही के दौरान 13.7 फीसदी बढ़कर 5092 करोड़ रुपये हो गई जोकि इससे पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 4772 करोड़ रुपये थी। एयरलाइन की स्टैंड-अलोन इनकम 16 फीसदी बढ़कर 4101 करोड़ रुपये से बढ़कर 4772 करोड़ रुपये हो गई।

इसके बेड़े में कुल 113 विमान हैं, जिनमें से 26 एयरलाइन के खुद के हैं जबकि 87 लीज पर हैं।

मोदी जी की दिलचस्पी क्यों

मोदी जी इस एयरलाइंस को बचाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं ? क्या जेट एयरवेज कोई सरकारी कम्पनी है ? जबकि सरकारी संपत्ति एयर इंडिया की तो सम्पत्ति तक टुकड़े-टुकड़े करके बेचने की योजना है लेकिन जेट एयरवेज का एकसाथ ही पूरा सौदा करने का टाटा पर दबाव बनाया जा रहा है आखिर क्यों ?

क्या इसका कारण यह है कि जेट के मालिक नरेश गोयल को मोदी सरकार ने 2015 में पीएनबी से एक बड़ा लोन दिलवाया है ? मोदी जी नहीं चाहते कि चुनावी साल में नरेश गोयल भी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरह सारा पैसा डकार ले। पहले अपने चहेते उद्योगपति को बेहिसाब कर्ज दो और फिर चुनावी साल में उसके सेटलमेंट कराते रहो।

सीधी ओर सच्ची बात तो यह है कि अगले 6 महीने में ही मोदी जी को आम चुनाव का सामना करना है। नरेश गोयल को वह एक और नीरव मोदी और विजय माल्या बनना देना नहीं चाहते।

राम नाम की लूट है, हो सके तो रिजर्व बैंक को जी भरकर लूट

रिजर्व बैंक की सरप्लस पूंजी से कई और विजय माल्या, कई और नीरव मोदी-मेहुल चौकसी पैदा करने की तैयारी

3.7 लाख करोड़ के नए बैंक कर्ज़ आरएसएस और बीजेपी समर्थक उद्योगपतियों को बांटे जाएंगे

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली – मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक हाल ही में मुंबई में हुई। इस बैठक को लेकर पूंजीवादी मीडिया यह बताने में लगा हुआ है कि इस बैठक में कौन ज्यादा झुका, कौन कम झुका...कौन जीता और कौन हारा... वह यह भी बता रहा है कि इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए लेकिन मीडिया का कोई वर्ग यह बताने को तैयार नहीं है कि जो फैसले लिए गए हैं, उसका भारतीय बाजार, अर्थव्यवस्था और यहां की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बैठक के बारे में जिस ईमानदार विश्लेषण की जरूरत है, वह कोई करने को तैयार नहीं है। आरएसएस समर्थक मीडिया तो उल्टा कई सारे तथ्यों को दबाने में जुटा है।

...तो यह रहा केंद्र सरकार और आरबीआई बोर्ड की बैठक का नतीजा...

मोदी सरकार ने रिज़र्व बैंक पर दबाव डालकर बैंकों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में 0.625 प्रतिशत की वृद्धि को 2020 तक के लिए टलवा दिया। अब बिना नई पूंजी डाले (जो सरकार डालने की स्थिति में नहीं है) बैंक 3.7 लाख करोड़ के नए कर्ज़ दे पाएंगे। रिज़र्व बैंक ने ये भी मान लिया कि लघु-मध्यम उद्योगों को कर्ज़ देने की शर्तों में ढील दी जाएगी और वसूली न होने पर भी 25 करोड़ रु तक के कर्ज़ को तुरंत एनपीए घोषित करने से बचाव के उपाय किए जाएंगे।

बैंक नए कर्ज़ देंगे, उन्हें जल्दी एनपीए घोषित नहीं करेंगे तो कुल कर्ज़ की तादाद बढ़ जाएगी, एनपीए की नहीं बढ़ेगी, तो एनपीए का ब्र घट जाएगा, बैंक ऊपरी तौर पर स्वस्थ नजर आने लगेंगे। सरकार दावा कर सकेगी कि उसने वित्तीय व्यवस्था को संकट से निकाल लिया। उद्योग भी नई नकदी मिलने से कुछ वक्त तक सेहतमंद नजर आने लगेंगे, कर्ज़ की वसूली का दबाव घटने से अतिरिक्त फायदा होगा। नोटबंदी/जीएसटी के बाद से बेचैन संघ समर्थक टटपूंजिया सरमायेदार तबक़ा चुनाव के वक़्त खुश और अहसान से दबा होगा।

लेकिन क्या नए कर्ज़ देने से उद्योगों की समस्या दूर हो जाएगी ?

पिछले सप्ताह ही एसबीआई, मॉर्गन स्टेनली, सीएलएसए, एमके ग्लोबल, आदि के विश्लेषण के आधार पर कहा गया था कि असली समस्या औद्योगिक मुनाफ़े की दर का कम होना है जो लगातार 10 वर्षों से गिर रही है क्योंकि पूंजी का निवेश जिस बड़े पैमाने पर किया गया है उत्पादन का स्तर उसके मुक़ाबले नहीं बढ़ पा रहा और औसत प्रति इकाई पूंजी पर मुनाफा लगातार नीचे जा रहा है, लघु-मध्यम उद्योगों के लिए तो 5-6 प्रतिशत पर जा पहुंचा है।

पर, बैंक कर्ज़ पर ब्याज तो पूंजीपति उत्पादन से प्राप्त मुनाफ़े में से ही चुकाता है। यह ब्याज दर अब लगभग 9-10 प्रतिशत है। उद्योग में लगी पूंजी का लगभग 80 प्रतिशत बैंक, आदि वित्तीय पूँजीपतियों से ही आता है। मगर कुल पूंजी पर उत्पादन से लाभ दर 5-6 प्रतिशत हो तो 80 प्रतिशत वित्तीय पूंजी पर 9-10 प्रतिशत की दर से ब्याज कैसे चुकाया जाए? यही औद्योगिक-वित्तीय दोनों संकट के मूल में है। जिसका शिकार कुछ इजारेदार पूँजीपतियों को छोड़कर सब हो रहे हैं। 2-3 साल पहले तक अमेरिकी-यूरोपीय-जापानी केंद्रीय बैंकों द्वारा अथाह नकदी प्रवाह से विश्व थोक पूंजी बाजार में ब्याज दरें लगभग शून्य तक पहुँच गईं थीं तब बड़े पैमाने पर भारतीय पूँजीपतियों (बैंक-उद्योग दोनों) ने विदेशी मुद्रा में सस्ते ब्याज पर ऋण लेकर संकट को टाला था, मगर अब वहाँ भी ब्याज दर बढ़ रही है, साथ में डॉलर भी महंगा हो रहा है; दोनों के संयुक्त प्रभाव से अब उस कर्ज़ की लागत भी 8-10 प्रतिशत तक पहुँच रही है।

अत: सरकार बैंकों की तिजोरी का मुंह खोलकर जो नकदी डालेगी और उसकी वसूली में छूट देगी, वह तात्कालिक राहत ही होगी, क्योंकि वसूली अनिश्चित काल तक तो टाली नहीं जा सकती। लेकिन उत्पादन में विस्तार की गुंजाइश कहाँ है? खरीदार कहाँ है? मुनाफा बढ़ेगा कैसे? श्रमिकों को और कम मजदूरी देकर, कम श्रमिकों से ही ज्यादा उत्पादन कराकर भी मुनाफ़े को कितना बढ़ाया जा सकता है जब मजदूरी पहले से ही बहुत कम है, पहले से ही श्रमिकों का खून बेइंतहा निचोड़ा जा चुका है।

मुनाफा नहीं बढ़ेगा, पूंजी और बढ़ जाएगी, तो मुनाफा दर और नीचे ही जाएगी, कर्ज़ चुकाए नहीं जा सकेंगे, उद्योग व बैंक दिवालिया होंगे ही, इसको कुछ वक्त के लिये टाला जा सकता है, अनिश्चितकाल के लिए नहीं। संकट पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में है, नकदी डालने से यह हल नहीं हो सकता।